भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 08 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के आठ चरणों का कार्यवृत।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के आठ चरणों का आयोजन दिनांक 15 से 18 फरवरी, 2022 को राजभाषा विभाग, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी मंत्रालय/विभागों के कार्यों की समीक्षा करना है। कॉलिक की 43वीं बैठक में सभी मंत्रालयों/विभागों ने अपनी शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की, इस हेतु सभी का अभिनन्दन।

इस समीक्षा बैठक में सभी मंत्रालय/विभागों द्वारा प्रेषित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचनाओं की समीक्षा की गई, कमियों को चिन्हित किया गया, लक्ष्यों में आई कमी पर चर्चा की गई, तथा सुधार हेतु सभी विचारों को साझा किया गया। बैठक के कार्यवृत को राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in के अद्यतन सूचनाएं लिंक पर देखा जा सकता है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में पाई गई कमियां, राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर 01 माह के अंदर अनुवर्ती कार्रवाई कर राजभाषा विभाग को सूचित करें।

08/04/2022
(बी.एल.मीना)
निदेशक(का.)
दूरभाष: 23438143

संलग्न: यथोपरि

प्रति:-

1. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित मंत्रालय/विभाग (सूची संलग्न) के संयुक्त सचिव (प्रशा.)
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव(रा.भा) के निजी सचिव।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

विषय: केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति और वार्षिक कार्यक्रम के मदों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉलिक) की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2020-21 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कॉलिक की 43वीं बैठक का आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी, 2022 के बीच सचिव राजभाषा विभाग, **श्रीमती अंशुली आर्या** की अध्यक्षता में किया गया।

2. 43वीं कॉलिक के प्रथम चरण की बैठक 15 फ़रवरी से 18 फ़रवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11.00-1.00 बजे तथा द्वितीय चरण की बैठक अपराह्न 3.00-5.00 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि, दिनांक 15 फ़रवरी, 2022 को दोनों चरणों की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** के माध्यम से तथा दिनांक 16 फ़रवरी – 18 फ़रवरी, 2022 की बैठक प्रत्यक्ष रूप में सम्मेलन कक्ष, एन.डी.सी.सी-2 भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए उक्त बैठक में पूर्वाह्न एवं अपराह्न 10-10 मंत्रालयों/विभागों (**सूची अनुलग्नक 'क' पर**) के संयुक्त सचिवों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची **अनुलग्नक 'ख'** पर उपलब्ध है।

4. सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि "केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में एक बैठक आयोजित की जाती है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा संबंधी कानूनी प्रावधानों, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत सिफारिशों की समीक्षा/आदेश आदि की चर्चा/समीक्षा करना है"। इससे पूर्व सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में इस प्रकार की 42 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सचिव महोदया ने कहा कि गृह मंत्री जी के राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में समय-समय पर दिये गए ओजस्वी व्याख्यानों से प्रेरित हो, मंत्रालयों का नेतृत्व कर रहे मंत्रीगण वास्तव में हिंदी प्रेमी होने के साथ-साथ मिसिलों पर हिंदी में कार्य को महत्व दे रहे हैं। अतः हमें हिन्दी में कार्य करने के अभ्यास को बढ़ावा देना है। संविधान के अनुच्छेद 343 तथा 351 को सचिव महोदया द्वारा संदर्भित किया गया।

5. बैठक के प्रत्येक दिन अपने सम्बोधन में सचिव, राजभाषा विभाग ने सभी भाग ले रहे अधिकारियों से विशेष आग्रह किया कि वह कार्यालयी कार्यों हेतु हिंदी के सरल शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करें जो बोधगम्य हों, क्लिष्ट न हों। सरल भाषा के प्रयोग के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य माध्यमों से भी राजभाषा विभाग को निदेश प्राप्त होते रहे हैं, उसका उल्लेख भी सचिव महोदया द्वारा किया गया। सभी मंत्रालय दिल्ली में 'क' क्षेत्र में होने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय एवं विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रेरणा का स्रोत होने चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी के प्रयोग के संबंध में अपने कनिष्ठ अधिकारियों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। साथ ही कार्यालय में प्रोत्साहन योजनाओं, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन देना चाहिए।

6. सचिव महोदया द्वारा राजभाषा अधिनियम, नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की मॉनिटरिंग करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्रालयों/विभागों ने वर्ष 2020-21 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से जो आंकड़े एवं तथ्य राजभाषा विभाग को भेजें हैं, उनकी समीक्षा बैठक में की जाएगी, जिसके उपरांत हम सभी अपनी कमियों को सुधारेंगे और अपने-अपने मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी कामना है, क्योंकि कॉलिक की बैठक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से मंत्रालयों/विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद से राजभाषा के प्रयोग में आ रही समस्याओं को हम समझ सकते हैं और अपने-अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

7. सचिव महोदया ने कहा कि संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। इसी क्रम में उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के पूर्ण द्विभाषीकरण पर ज़ोर दिया और साथ ही यह भी कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अधिकांश कार्यालय ई-ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं, अतः उस पोर्टल को भी द्विभाषी कार्य हेतु सुलभ बनाया जाए। इसके अतिरिक्त मंत्रालय/विभाग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिन बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, उनमें कार्यालय/विभाग का नाम पृष्ठपट (बैकड्राप) में द्विभाषी रूप में दर्शाया जाए।

8. सचिव महोदया के अध्यक्षीय सम्बोधन के उपरांत, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा पुनः सभी अधिकारियों का अभिनन्दन किया गया और अपना परिचय देने का अनुरोध किया गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन अपने कार्यालयों में सुनिश्चित करवाएं और राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। संयुक्त सचिव महोदया ने, क्रमवार राजभाषा हिंदी के अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हुए कहा कि वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन अपने-अपने मंत्रालय /विभाग में सुनिश्चित तो करें ही, साथ ही हिंदी के प्रयोग में उत्तरोतर वृद्धि के लिए भी निरंतर प्रयास करें। अपने-अपने मंत्रालय/विभाग में प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तकों, विशेष सूचनापत्र से राजभाषा विभाग को अवगत कराएं। उन्होंने कहा, समय-समय पर राजभाषा सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं का आयोजन विभाग द्वारा किया जाता है, उसी तरह मंत्रालय भी अपने और अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों, सम्मेलनों की शुरुआत करें और राजभाषा विभाग को सूचित करें।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया:-

क) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं – अनुवाद, लघु फिल्म, कंठस्थ के संबंध में सूचित किया गया और सभी को प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी प्रविष्टियाँ समय से भिजवाने को कहा गया।

ख) सभी मंत्रालयों/विभागों को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की सूचना प्राप्त होते ही अपने विभाग/कार्यालय स्तर पर प्रभावोत्पादक प्रसारण करने और राजभाषा से जुड़े अधिकारियों का अनिवार्य नामांकन समय से विभाग को भिजवाने पर बल दिया गया।

ग) सभी मंत्रालयों को सलाहकार समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित करने के निदेश दिये गए।

घ) सभी मंत्रालयों/विभागों से उनके द्वारा राजभाषा हिंदी के संबंध में आयोजित विशेष कार्यक्रमों की सूचना राजभाषा विभाग को अवगत कराने को कहा गया और राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा उन कार्यक्रमों में सकारात्मक भागीदारी की बात कही गई।

ङ) कॉलिक की बैठकों में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति की बात कही गई।

सभी प्रतिभागियों के परिचय एवं मुख्य बिन्दुओं के साझा किए जाने के उपरांत संयुक्त सचिव, महोदया ने निदेशक (कार्यान्वयन) को बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए बारी-बारी से सभी मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा मंत्रालयों/विभागों की पीपीटी के माध्यम से करने को कहा।

9. राजभाषा विभाग के निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा पॉवर प्वांइट प्रस्तुतीकरण दिया गया और मंत्रालयों/विभागों से की जा रही अपेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषी जारी किए जाने अपेक्षित हैं। साथ ही, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

10. उन्होंने इस बात पर सभी प्रतिभागियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया कि यदि कोई कार्यालय धारा 3(3) का अनुपालन नहीं करता है तो वह राजभाषा विभाग की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों के मूल्यांकन से पूर्णत: वंचित हो जाता है। साथ ही, यदि कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं करता है तो पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय उसके 10 नंबर काट लिए जाते हैं जिससे वह पुरस्कारों की श्रेणी से लगभग बाहर हो जाता है अथवा दूसरे कार्यालयों के मुकाबले, राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने में, उसका स्थान नीचे हो जाता है।

11. (i) निदेशक (कार्यान्वयन) ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया:-

क) वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

ख) अंग्रेजी वेबसाइट और हिंदी वेबसाइट का साथ-साथ अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

ग) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल रुप से हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कनिष्ठ अधिकारी उदाहरण ले सकें।

घ) अभ्यास आधारित कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए

ङ) प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कार्मिकों को यथाशीघ्र प्रशिक्षित करवा देना चाहिए, क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा 2025 तक सभी को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन्हें इन प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें।

च) जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है,वहां शीघ्र गठन/पुनर्गठन आवश्यक है ताकि इसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा सकें।

छ) सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्मिकों को हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, केवल उन्हें यूनिकोड समर्थित करने की आवश्यकता है।

ज) अपने-अपने कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का प्रत्येक तिमाही में नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

झ) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी नियमित रूप से कराया जाना चाहिए।

(ii) निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा विशेष रूप से सभी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया कि ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा अर्थात एक महीने के अंदर प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर सही ढंग से, विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षरित, प्रमाण-पत्र एवं मुहर सहित अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। उप निदेशक (तकनीकी) द्वारा निदेशक महोदया के तिमाही प्रगति रिपोर्ट के समय से और सही भरे जाने की बात को सविस्तार समझाया गया कि मंत्रालय/विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की सामायिकता और विशुद्धता के आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट, कार्यालय में राजभाषा के कार्यों को परिलक्षित करती है। इस रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली को भरे जाने में सहायक होते हैं और इस रिपोर्ट की विशुद्धत्ता मंत्रालय/विभाग को रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्रदान किए जाने हेतु पात्र बनाता है। अंतिम तिथि से एक महीने (30 दिन) के भीतर यह रिपोर्ट भेजने पर 6 अंक मिलते हैं, 30-60 दिनों के भीतर भेजने पर 3 अंक मिलत हैं और 60 दिनों से अधिक समय पश्चात भेजने पर -6 अंक मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप पुरस्कार जीतने की संभावना कम हो जाती है।

12. 43वीं कॉलिक बैठक में सामने आए मुद्दे एवं आदेशों का अनुपालनार्थ सारांश-:

i) हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की समयबद्धता और आंकड़ों की परिशुद्धता पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रमुखतः धारा 3(3) और नियम-5 के अनुपालन पर ज़ोर दिया गया।

ii) तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार श्री केवल कृष्ण से संपर्क किया जाना।

iii) विभाग द्वारा केन्द्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु तीन प्रतियोगिताओं के आयोजन की सूचना दी गई:-
   क) अनुवाद प्रतियोगिता
   ख) राजभाषा संबंधी कार्य को प्रेरित करने वाली लघु वीडियो फिल्म प्रतियोगिता।
   ग) 'कंठस्थ' का ग्लोबल डाटा बेस सुदृढ़ करने हेतु प्रतियोगिता।

iv) बनारस में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों से पधारे अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद किया गया और आने वाले ऐसे सम्मेलनों में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालय स्तर पर सूचना का विस्तृत प्रसारण किए जाने के निदेश दिये गए। साथ ही, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालय के प्रमुखों से राजभाषा सेवा से जुड़े अधिकारियों को उनके दायित्व का भान करवाते हुए अनिवार्य रूप से समय पर नामांकन कर अनुमति प्रदान किए जाने को कहा गया। राजभाषा के अनुपालन, प्रचार-प्रसार में अग्रसर और महत्वपूर्ण काम कर रहे अन्य इच्छुक अधिकारियों का भी चुनाव कर हिन्दी अधिकारियों के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जा सकता है, यह सूचना दी गई।

v) हिंदी सलाहकार समिति का गठन एवं वर्ष में दो बैठकें सुनिश्चित किए जाने पर विशेष बल दिया गया।

vi) मंत्रालयों/विभागों में शत प्रतिशत हिंदी में कार्य कर रहे अधिकारियों के नाम राजभाषा विभाग को भेजे जाने को कहा गया। ये नाम दो श्रेणियों में हो सकते हैं :-

क) हिंदी में शत प्रतिशत कार्य करने वाले उप सचिव एवं उच्चतर अधिकारी।

ख) हिंदी में शत प्रतिशत कार्य करने वाले अन्य अधिकारी/कर्मचारी।

इन अधिकारियों/कर्मचारियों के शत प्रतिशत कार्य का औचक निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी किया जा सकता है। अतः नाम पूर्णतः सही एवं विभागाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र द्वारा सत्यापित हों, ऐसी सूचना दी गई।

vii) वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी करने और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी संस्करण को भी साथ ही साथ अद्यतन किए जाने के आदेश दिये गए। इस संबंध में राजभाषा विभाग का तकनीकी अनुभाग प्रशिक्षण भी दे सकता है।

viii) कंप्यूटर पर यूनिकोड का अनिवार्य प्रयोग और ई-ऑफिस में भी हिंदी के प्रयोग पर ज़ोर दिया गया।

ix) राजभाषा हिन्दी का अल्पज्ञान रखने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का हिंदी में प्रशिक्षण सुनिश्चित करवाया जाना।

x) हिंदी के कार्य की अधिकता को देखते हुए मंत्रालयों/विभागों को अपने स्तर से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा गया। जिसके उपरांत राजभाषा विभाग द्वारा उन पदों को संवर्गित (cadre) किए जाने के अनुरोध पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाने की बात कही गई।

xi) मंत्रालयों /विभागों/कार्यालयों में अनुवाद कार्य में सहयोग देने के आशय से विद्वानों का एक पैनल, जो आवश्यकता अनुसार अपनी सेवाएँ दे सकें, राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई।

xii) भविष्य में आयोजित होने वाली कॉलिक की बैठकों में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के अधिकारी ही अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। चूंकि, इस बैठक की अध्यक्षता सचिव राजभाषा द्वारा की जाती है और संयुक्त सचिव मंत्रालय/विभाग की कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं, अतः बैठक में ज्ञात होने वाली कमियों को अपने नेतृत्व में, राजभाषा नियमों का सुचारू अनुपालन उनके द्वारा सुगमता से किया जा सकता है।

13. इसके उपरांत मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिवों/ प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, तिमाही प्रगति रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों तथा उक्त मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट के हिंदी संस्करण की समीक्षा की गई। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में मंत्रालय/विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ब्यौरा परिशिष्ट 'क' से 'घ' पर है। साथ ही मंत्रालय/विभागवार समीक्षा के मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-

13.1 अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग के विशेष कार्य अधिकारी ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और राजभाषा विभाग के सुझावों को नोट कर पूर्ण करने संबंधी आश्वासन दिया। विभाग के अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अंतरिक्ष विभाग ने वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें देश भर से कुल 108 शोध पत्र पढ़े गए। तिमाही को भरवाने की दिशा में विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है और विभाग की द्विभाषी वेबसाइट को अद्यतित करने के साथ साथ हिंदी टैब बनाने का आश्वासन दिया। साथ ही खाली पदों को भरने हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हेतु विज्ञापन दिया गया है और टंकक के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन देने की तैयारी है। अंतरिक्ष विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।

13.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारी ने अपने मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया की मंत्रालय का कार्य लाभकारी योजनाओं पर केन्द्रित है और स्वीकृति पत्र पोर्टल से ही निकलते है जो केवल अंग्रेजी भाषा में है। सभी योजनाओं को पोर्टल पर हिंदी में डाले जाने का प्रयास है विशेष रूप से 'क' और 'ख' क्षेत्र में हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण यह अभी संभव नहीं हो पा रहा परंतु मंत्रालय द्वारा इस दिशा में प्रयास किये जा रहा है। अधिकारी ने सूचित किया कि नए सत्र से सारे स्वीकृति पत्र हिंदी में अनूदित करेंगे। साथ ही आंकड़ों को लक्ष्य तक पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।

13.3 आयुष मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया कि पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेंगे। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया की वेबसाइट के दो यू.आर.एल. है, एक वेबसाइट पर बोझ बढ़ जाने के कारण दूसरी वेबसाइट भी प्रयोग में लाई जाती है जिसे हिंदी भाषा में अद्यतित रखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही सलाहकार समिति के विषय में मंत्रालय के अधिकारी ने सूचित किया की गठन प्रक्रियाधीन है।

13.4 आर्थिक कार्य विभाग

विभाग के अधिकारी ने बताया की क, ख, ग क्षेत्र में पत्राचार के कम प्रतिशत की समीक्षा की जाएगी तथा पत्राचार के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उनके मंत्रालय में रिक्त पदों की जो स्थिति है, उसके विषय में अवगत कराया। साथ ही यह भी बताया गया कि सेबी (बोर्ड) आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत है जो स्वयं को भारत सरकार का कार्यालय नहीं मानता जबकि अधिसूचित विभाग से करवाने की चेष्टा है। उपस्थित अधिकारी ने रिक्त पदों के संबंध में

जानकारी दी। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है तथा इस माह संकल्प जारी करने की सूचना दी। विभाग के अधिकारी ने आर्थिक मामलों पर मार्च के बाद संगोष्ठी का आयोजन करने की बात कही।

13.5 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ो पर सहमति व्यक्त की तथा उन्होंने बताया कि मंत्रालय में हिंदी के कुछ पद खाली हैं जिसके कारण कार्य लंबित हो जाता है तथा पत्राचार लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने आगे बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है। वेबसाइट के विषय में अधिकारी ने सूचित किया कि वेबसाइट की सभी त्रुटियों को ठीक करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

13.6 इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और बताया कि हिंदी में पत्राचार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उपस्थित अधिकारी ने हिंदी जानने वाले उच्च अधिकारियों के संबंध में संशोधित आंकड़े भेजने का आश्वासन दिया। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। अधिकारी ने कहा चूंकि मंत्रालय का कार्य तकनीकी प्रकृति का है इसलिए पत्राचार में बढ़ोत्तरी धीरे-धीरे होगी। क्लिष्ट शब्दों को सरलीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वेबसाइट के विषय में उपस्थित अधिकारी ने बताया कि विदेशी यूजर होने के कारण वेबसाइट अंग्रेजी में है जिसे अद्यतित करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। संयुक्त सचिव ने बताया की उनके मंत्रालय में टेक्नोलॉजी खंड है जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी कार्य किया है तथा वे एक रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भी भेज रहे हैं। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.7 इस्पात मंत्रालय

मंत्रालय से उपस्थित अधिकारी ने पत्राचार के आंकड़ों में दर्शायी गई कमी पर सहमति व्यक्त की। प्रतिनिधि ने बताया कि टंकण से सम्बंधित आंकड़ों में त्रुटि है, जबकि मंत्रालय के रिकॉर्ड में सही आंकडें दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में प्रत्येक शुक्रवार को एक परंपरा शुरू की गयी है जिसमें हिंदी अनुभाग के अधिकारी प्रत्येक अनुभाग में जाकर हिंदी में काम करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी के साथ अधिकारी ने सूचित किया कि कोई भी अनुभाग यदि अनुवाद कार्य करता है तो NIC पर स्वयं अपलोड करा सकता है। मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी है। मंत्रालय द्वारा कार्यशालाएं/ संगोष्ठियाँ राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गयी हैं। कोविड महामारी के कारण इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 01 बैठक हो चुकी है।

13.8 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से उपस्थित अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट में दिखाए गये आंकड़ों पर सहमति व्यक्त की। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय का ज्यादातर पत्राचार 'ग' क्षेत्र यानि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के साथ ही होता है जिसके कारण मंत्रायल पत्राचार में निर्धारित लक्ष्यों से पीछे है। भविष्य में पत्राचार को बढ़ाने हेतु आश्वासन दिया गया। उपस्थित अधिकारी ने बताया कि एन.आई.सी. की बैठक में मंत्री जी द्वारा हिंदी भाषा को कार्यसाधक बनाने पर लगातार ज़ोर दिया जाता है, जिससे मुख्य धारा के साथ सभी लोग सम्मिलित हो सकें। मंत्रालय के अधिकारी ने रिक्त हिंदी पदों के संबंध में भी जानकारी दी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.9 उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग की चारों तिमाही की **रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।** उपस्थित अधिकारी ने बताया कि कार्यान्वयन के कार्य से बहुत परिचित नहीं है। समयानुसार कार्य को सीखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं तथा तिमाही रिपोर्ट अपलोड करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने सभी कमियों को सुधारने का आश्वासन दिया। अधिकारी द्वारा विभाग के रिक्त पदों की जानकारी दी गई । उपभोक्ता मामले विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।

13.10 उर्वरक विभाग

उर्वरक विभाग के अधिकारी ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा आश्वासन दिया की पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगें। तकनीकी प्रवृति का कार्य होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके परन्तु पिछले एक वर्ष में थोड़ी प्रगति हुई है। उर्वरक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से आए प्रतिनिधि ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा विभाग के हिंदी कार्य संबंधित प्रतिशत को लक्ष्य के अनुरूप बना कर रखने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने जानकारी दी कि विभाग में सारा कार्य ई-ऑफिस में किया जाता है तथा पखवाड़ों का आयोजन भी ऑनलाइन किया जाता है। वेबसाइट के विषय में अधिकारी ने बताया कि विभाग अपनी वेबसाइट का पाक्षिक निरीक्षण करता है तथा अद्यतित करने का प्रयास भी निरंतर करते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

13.12 औषध विभाग

औषध विभाग के अधिकारी ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया की सचिव, औषध विभाग ने भी ज्यादातर कार्य हिंदी में करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। टंककों के विषय पर प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि ज्यादातर टंकक ठेके पर नियुक्त हैं जिन्हें हिंदी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेबसाइट को भी अद्यतित करने का हेतु औषध विभाग ने NIC को संपर्क करने का आश्वासन दिया है। औषध विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.13 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति जताई तथा पत्राचार में आई कमी के विषय में बताया कि कोविड महामारी के कारण उनके विभाग के ज्यादातर अधिकारी/कर्मचारी घर से ही कार्य का निष्पादन कर रहे थे। जून, सितम्बर और दिसंबर की तिमाही में सुधार आया है। वेबसाइट के विषय में अधिकारी ने जानकारी दी है कि अनुदित सामग्री को पूसा कार्यालय भेजकर वेबसाइट को अद्यतित करवाया जायेगा तथा राजभाषा विभाग को जानकारी भेजी जाएगी। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.14 कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। विभाग के अधिकारी ने पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा इस विभाग को कीर्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अधिकारी ने अवगत करवाया कि उनके विभाग की वेबसाइट में कुछ समस्या है जिसके लिए NIC से संपर्क किया जायेगा। साथ ही अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट के द्विभाषीकरण हेतु अनुबंध के आधार पर अनुवादक रखने पर भी विचार किया गया परंतु टेंडर के अंतर्गत ऊंची दर के कारण अनुवादक नहीं रख सके। रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी दी गई। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.15 कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पत्राचार को सचिव द्वारा सराहा गया। उपस्थित अधिकारी ने रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी तथा उन्हें नियमित पदों द्वारा भरने का निवेदन किया। निदेशक (प्रशासन), राजभाषा विभाग द्वारा आरटीआई के संबंध में जवाब भेजने तथा शिकायत का निवारण करने को कहा गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

13.16 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाने का आश्वासन दिया। विभाग की वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुर्नगठन हो गया है। समिति की 01 बैठक संपन्न हो चुकी है।

13.17 कोयला मंत्रालय

कोयला मंत्रालय ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। अधिकारी के वेबसाइट को जल्दी ही अद्यतित करने का आश्वासन दिया। कोयला मंत्रालय ने हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें जल्दी ही संपन्न की जाएँगी।

13.18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा बताया कि कोविड के कारण विभाग के पत्राचार का प्रतिशत कम रहा। विभाग की वेबसाइट हिंदी में खुलती है। विभाग के अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने हेतु निवेदन किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुर्नगठन हो चुका है तथा समिति की बैठक होने वाली है।

13.19 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा जानकारी दी कि तकनीकी प्रकृति का कार्य होने के कारण पत्राचार का प्रतिशत कम है जिसे भविष्य में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अधिकारी ने आंकड़ो को संशोधित करने की भी बात कही। वेबसाइट के विषय में उन्होंने बताया कि वेबसाइट संबंधी सूचनाओं को संशोधन के उपरांत वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन हो चुका है।

13.20 उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)

मंत्रालय के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा जानकारी दी कि तकनीकी ख़राबी के कारण तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं कर सके। दिसंबर की तिमाही ऑनलाईन माध्यम से भेजने का आश्वासन दिया। वेबसाइट को भी क्रमवार ठीक करने की बात कही। मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी कि स्कूल शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग को दस्तावेज़ अद्यतित करने के लिए भेजा है, जिसके उपरांत उन सभी दस्तावेजों का अनुवाद किया जायेगा और वेबसाइट पर भी

अपलोड करवाने का आश्वासन दिया। रिक्त पदों के संबंध में भी अधिकारी ने निवेदन किया है कि नियमित पदों से भर दिया जाये। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.21 खान मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा अधिकारी ने आंकड़ों की विसंगतियों को ठीक करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सूचित किया कि वेबसाइट को अद्यतित करने का कार्य चल रहा है तथा सभी सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध होंगी। सभी टेंडर द्विभाषी रूप से निकाले जाते है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.22 ग्रामीण विकास विभाग

विभाग के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा अधिकारी ने आंकड़ों की विसंगतियों को ठीक करने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारी ने सूचित किया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार की प्रतिशतता के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण हुआ था जिसमें अधिकारियों को हिंदी में पत्राचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वेबसाइट के संबंध में अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट को अद्यतित करने का कार्य एन.आई.सी. के स्तर पर लंबित है। अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने का भी निवेदन किया है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

13.23 गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों में पत्राचार के लक्ष्यों से पीछे होने के विषय में बताया कि हमारे यहाँ प्रदर्शित आंकड़ों से ज़्यादा काम होता है। वेबसाइट के विषय में उन्होंने बताया कि वे जल्द ही एन.आई.सी. से बैठक कर वेबसाइट को अद्यतित करवाएंगे। गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। समिति की बैठक दिनांक 20/10/2021 को गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है।

13.24 जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ों में कमी के बारे में बताया गया कि हिंदी में कार्य तो बहुत होता है परन्तु आंकड़े ठीक से भरे नहीं गए, भविष्य में ठीक करने का आश्वासन दिया। विभाग के अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट को हिंदी में अद्यतित करवाने हेतु जल्द ही एन.आई.सी. से सम्पर्क करेंगे। मंत्रालय के अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने हेतु निवेदन किया। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

13.25 जल संसाधन मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने आंकड़ों की विसंगति को ठीक करने का आश्वासन दिया तथा इस संबंध में एक आंतरिक बैठक करने की बात कही साथ ही यह भी बताया कि 8 से 10 अनुभाग रिपोर्ट नहीं भेजते है जिसके कारण पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य से कम हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी में काम करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अधिकारी ने वेबसाइट के संबंध में जानकारी दी कि वेबसाइट को भी अद्यतित करने का प्रयास करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा बैठकें प्रस्तावित हैं।

13.26 डाक विभाग

डाक विभाग के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग के सभी उच्च अधिकारी पूरा काम हिंदी में करते हैं। विभाग को पुरस्कृत भी किया गया है। अधिकारी ने वेबसाइट को जल्द ही द्विभाषी रूप से अद्यतित करने का आश्वासन दिया। डाक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.27 दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग की चौथी तिमाही की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आंकड़ें भी बेहतर नहीं है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि तकनीकी विभाग होने के कारण टिप्पणी हिंदी में करना संभव नहीं है। उन्होंने रिक्त पदों को भरने का निवेदन भी किया। वेबसाइट को भी जल्द ही अद्यतित करने का आश्वासन दिया। दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

13.28 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की बात को स्वीकार किया। अधिकारी ने इन सभी विसंगतियों को आगामी तिमाही में दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही वेबसाइट की कमियों को भी ठीक करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने का निवेदन किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.29 न्याय विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा आश्वासन दिया कि आंकड़ें और बेहतर करेंगे। अधिकारी ने बताया की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की त्रुटियों को जल्द ही ठीक करेंगे। अधिकारी ने सूचित किया कि विभाग की नई वेबसाइट बन रही है तथा सिटिजन चार्टर पर भी कार्य किया जा रहा है। जल्द ही वेबसाइट को अद्यतित करने का प्रयास करेंगे। हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

13.30 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा बताया कि वैज्ञानिक प्रकृति का कार्य होने के कारण आंकड़ें पत्राचार के लक्ष्यों से कम हैं। अधिकारी द्वारा जल्दी ही लक्ष्यों को बेहतर करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही अधिकारी ने वेबसाइट की कमियों को सुधारने का आश्वासन भी दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.31 वस्त्र मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा 'ग' क्षेत्र में पत्राचार में कमी की बात को स्वीकार किया। अधिकारी ने बताया कि वे अनुभागों का निरीक्षण करेंगे और आंकड़े बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट की सभी त्रुटियों को ठीक करने का आश्वासन भी दिया तथा यह भी बताया कि एन.आई.सी. के स्तर पर सूचनाओं को अपलोड करने का कार्य लंबित है। तकनीकी परामार्शदाता,एन.आई.सी. राजभाषा विभाग ने कहा कि अधिकारियों से निजी संपर्क करें तथा निरीक्षण के लिए ऑनलाइन प्रोफार्मा बनाएं। वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

13.32 नागर विमानन मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कार्यालय से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा घर से ही कार्य किया गया जिसके कारण आंकड़ों में कमी आई। अधिकारी ने कहा कि उनका मंत्रालय राजभाषा विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंकड़ों को और बेहतर करेंगे। वेबसाइट के विषय में अधिकारी ने सूचित किया कि नई वेबसाइट बनने की दिशा में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय में हर बुधवार हिंदी में कार्य करने के लिए हिंदी दिवस जैसा कार्यक्रम किया जाता है, जिस दिन मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्य करते है। इसके लिए एक स्लोगन भी दिया गया 'आज मैं हिंदी में काम करूंगा/करूंगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि मंत्रालय में नागर विमानन से संबंधित शब्दावली है जिसे वे राजभाषा विभाग के साथ साझा करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.33 निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा उन्होंने बताया की कोरोना महामारी के कारण कार्यालय से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा घर से ही कार्य किया गया जिसके आंकड़ों में कमी आई। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कोरोना की वजह से आंकड़ों

में कमी है। विभाग के अधिकारी ने आंकड़ों को सुधारने का आश्वासन दिया। निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन होना बाकी है।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट को अद्यतित करने के लिए कहा गया।

13.34 नीति आयोग

आयोग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा नियम 5 के उल्लंघन को स्वीकार किया। अधिकारी ने बताया कि आयोग में पचास प्रतिशत अधिकारी ठेके पर रखे गए हैं, जिस वजह से आंकड़ों में कमी है। आयोग द्वारा कार्यशालाओं के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। नीति आयोग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट को अद्यतित करने के लिए कहा गया।

13.35 पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा आश्वासन दिया कि आंकड़ों में दर्शायी गई कमी को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अधिकारी ने वेबसाइट को अद्यतित करने का आश्वासन दिया। पंचायती राज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट को अद्यतित करने के लिए कहा गया।

13.36 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा आंकड़ें को बेहतर करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने वेबसाइट के नवीनीकरण के विषय में जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा इस संबंध में मंत्रालय द्वारा संकल्प जारी किया जाना है।

संयुक्त सचिव ने वेबसाइट को अद्यतित करने की बात कही और की गयी कार्रवाई से राजभाषा विभाग को एक महीने में सूचना भेजने को कहा।

13.37 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मंत्रालय में हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता सराहनीय है। मंत्रालय को वर्ष 2019-20 में कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय से विभिन्न प्रकार की मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं जैसे मौसम-मंजूषा, जन-जन के लिए विज्ञान, भारत-भारती। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.38 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने आंकड़ों में आई कमी पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा बताया कि कोरोना महामारी की वजह से आंकड़े पत्राचार के लक्ष्य से कम हैं। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आंकड़ें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही वेबसाइट की त्रुटियों को तथा वेबसाइट को अद्यतित करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने का भी निवेदन किया, जिसपर निदेशक (कार्यान्वयन) ने प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट को अद्यतित करने तथा समिति का पुनर्गठन करने के लिए कहा गया।

13.39 परमाणु ऊर्जा विभाग

विभाग के अधिकारी ने बताया कि वैज्ञानिक प्रकृति का कार्य होने के कारण आंकड़ों में कमी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंकड़ें और बेहतर करेंगे। विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि विभाग में आयोजित सम्मेलनों में वैज्ञानिक हिंदी में बोलते हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि आप अपने यहां कार्यशाला करें जिसमें राजभाषा से संबंधित स्टॉल या प्रदर्शनी लगाएं और संगोष्ठी का आयोजन कर राजभाषा विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित करें। परमाणु ऊर्जा विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट को अद्यतित करने के लिए भी कहा।

13.40 पर्यटन मंत्रालय

तिमाही रिपोर्ट में दर्शाए गए हिंदी जानने वाले उच्च अधिकारियों से संबंधित मद संख्या 09 के आंकड़ों में विसंगति पायी गई जिसे संशोधित करने का आश्वासन अधिकारी द्वारा दिया गया। वेबसाइट को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में दूसरे मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि ई-ऑफिस तथा सोशल साइट्स पर हिंदी में किए गए कार्य या भेजे गए संदेश को हिंदी में गणना की जानी चाहिए। पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

संयुक्त सचिव ने कहा कि मंत्रालय में शत-प्रतिशत हिंदी में काम करने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों की सूची विभाग को भेजें जिन्हें गृह राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा सकें। संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वेबसाइट को अद्यतित करने के लिए कहा गया।

13.41 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उनके यहां सालाना 'पर्यावरण' नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उनके मंत्रालय में 'मेदिनी' नामक पुरस्कार योजना शुरू की गई है। उन्होंने वेबसाइट को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.42 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और बताया कि कोविड महामारी के कारण पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्यों से पीछे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट पर अंग्रेजी सामग्री को हिंदी करवाने का भी आश्वासन दिया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.43 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

विभाग के कार्यों की सराहना की गई। अधिकारी ने जानकारी दी कि सी.सी.एस. पेंशन नियमों को पूर्णत: हिंदी में अनुदित किया गया। साथ ही हिंदी की प्रगति हेतु विभाग के सभी अनुभागों का निरीक्षण भी किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.44 पशुपालन और डेयरी विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। पत्राचार के लक्ष्य अमूमन दोनों ही वर्षों में एक जैसे रहे। विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे आंकड़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट की कमियों को ठीक करने का भी आश्वासन दिया। पशुपालन और डेयरी विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुर्नगठन हो गया है।

13.45 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति जताई तथा आश्वासन दिया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आई कमी को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अधिकारी ने जानकारी दी कि मंत्रालय में हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.46 बायोटेक्नोलॉजी विभाग

विभाग के अधिकारी ने बताया कि आंकड़ों को भरने में कोई त्रुटि हुई है, जिसकी वे समीक्षा करेंगें। अधिकारी ने बताया कि वैज्ञानिक प्रकृति का कार्य होने के कारण आंकड़े थोड़े कम है। इसे हम और बेहतर करेंगे। विभाग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली भी प्रकाशित की गई है। अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने का निवेदन किया। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.47 भूमि संसाधन विभाग

विभाग के अधिकारी ने बताया कि पत्राचार का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। विभाग में इस संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। अधिकारी द्वारा रिक्त पदों को भरने का निवेदन किया गया। वेबसाइट में भी सुधार कर रहें हैं। भूमि संसाधन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.48 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों की सराहना की गई। विभाग की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

13.49 निर्वाचन आयोग

अधिकारी ने वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी करने हेतु आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 'राजभाषा स्मारिका' एवं 'महत्वपूर्ण है मत मेरा' नाम की पत्रिका का प्रकाशन होता है।

13.50 भारी उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आंकड़ों को सुधारने का आश्वासन दिया। वेबसाइट की कमी को भी जल्दी ठीक किए जाने का आश्वसन दिया। भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.51 मंत्रिमंडल सचिवालय

सचिवालय के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा बताया कि गोपनीय प्रकृत्ति का कार्य होने के कारण बहुत सी सामग्री को आंकड़ों में शामिल नहीं कर सकते। आंकड़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे।

13.52 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने आंकड़ों की विसंगति को ठीक करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने जानकारी दी कि वेबसाइट को भी जल्द ही द्विभाषी करा लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वर्तनी संबंधी प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता आदि चलाई जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

संयुक्त सचिव ने यथासंशोधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजने की बात कही।

13.53 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

अधिकारी ने नियम (5) के उल्लंघन पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा आश्वासन दिया कि इस त्रुटि को जल्द ही सुधार लिया जायेगा। वेबसाइट को भी अद्यतित तथा द्विभाषी करने का आश्वासन दिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

संयुक्त सचिव ने कहा कि एक माह के भीतर कमियों को दूर करके अपनी अनुवर्ती कार्रवाई राजभाषा विभाग को भेजें।

13.54 रक्षा उत्पादन विभाग

मंत्रालय के अधिकारी ने समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी। टिप्पणी के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई तथा वर्तमान तिमाही में नियम (5) के उल्लंघन के संबंध में आश्वासन दिया गया कि भविष्य में सुधार करेंगे। वेबसाइट को भी द्विभाषी कर अद्यतित करने का आश्वासन दिया। रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.55 रक्षा विभाग

रक्षा विभाग के आंकड़ों की सराहना की गई। अधिकारी ने वेबसाइट को अद्यतित करने का आश्वासन दिया। रक्षा विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.56 रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट को सराहा गया। अधिकारी ने जानकारी दी कि क्षेत्रीय रेल बोर्ड मूल कार्य का निष्पादन हिंदी भाषा में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा सभी उच्च अधिकारी शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं। वेबसाइट को अद्यतित करने का भी आश्वासन दिया। रेल मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुर्नगठन हो गया है।

13.57 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंकड़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट पर निरंतर काम जारी है, जो 2-3 माह के भीतर पूरा हो जाऐगा। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुर्नगठन हो गया है।

(२)

13.58 राजस्व विभाग

विभाग के अधिकारी ने लक्ष्यों में आई कमी पर सहमति व्यक्त की। वेबसाइट संबंधी त्रुटियों तथा कमियों को भी दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही इन्होंने अपने विभाग की चौथी तिमाही की रिपोर्ट को जांचने की बात भी कही। राजस्व विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

13.59 लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा आंकड़ों की विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही वेबसाइट को भी ठीक करने का आश्वासन दिया। लोक उद्यम विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.60 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

2020-21 की चौथी तिमाही की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस कमी को दूर करेंगे।

13.61 व्यय विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा इस संदर्भ में यह बताया कि कोविड महामारी की वजह से अधिकतर अधिकारियों/कर्मचारियों ने घर से ही कार्य निष्पादन किया जिसके कारण आंकड़ों में कमी आई है। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे आंकड़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तथा वेबसाइट की त्रुटियों को जल्दी ही संशोधित करेंगे। अधिकारी ने विभाग के रिक्त पदों को भरने का भी अनुरोध किया है। राजस्व, व्यय एवं विनिवेश विभाग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षाक कार्यालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

13.62 वाणिज्य विभाग

विभाग के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमती व्यक्त की तथा उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान घर से कार्य निष्पादन के कारण लक्ष्य से पीछे हैं। अधिकारी ने आंकड़ों के साथ-साथ वेबसाइट की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने रिक्त पदों के साथ-साथ उप निदेशक के पद को भरने का भी अनुरोध किया। अधिकारी ने जानकारी दी कि जेम पोर्टल को हिंदी में करने का प्रयास चल रहा है। वाणिज्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो चुका है।

13.63 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विभाग के अधिकारी ने टिप्पणी में आई कमी के संबंध में सहमति व्यक्त की। अधिकारी द्वारा इसे बेहतर करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने रिक्त पदों के साथ-साथ संयुक्त निदशक के रिक्त पद संबंधी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि विभाग की वेबसाइट अद्यतित की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.64 वित्तीय सेवाएं विभाग

विभाग के अधिकारी ने आंकड़ों में आई कमी दूर करने का आश्वासन दिया तथा बताया की कोविड के कारण पत्राचार के लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ा पीछे रह गए। अधिकारी ने वेबसाइट को अद्यतित करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने रिक्त पदों का भी उल्लेख किया। इनके यहां 08 उच्च अधिकारी शत-प्रतिशत हिंदी में काम करते हैं। प्रतिनिधि ने आग्रह किया कि विभाग के स्तर पर ई-टूल्स पर कार्यशाला कराई जाए। अधिकारी ने ई-टूल्स के संबंध में सुझाव मांगे जिन्हें क्लाउड पर साझा किया जा सके। वित्तीय सेवाएं विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.65 विद्युत मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने टिप्पणी के आंकड़ों में दर्शायी गई कमी पर सहमति व्यक्त की। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में आशुलिपिक व टंकक नए आए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आंकड़ों को बेहतर करने आश्वासन दिया। साथ ही वेबसाइट की कमियों को एक माह के अंदर दूर करने का आश्वासन दिया। विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.66 विदेश मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। अधिकारी ने जानकारी दी की मंत्रालय विदेशों में अधीनस्थ कार्यालयों में आईसीसीआर हिंदी चेयर्स की स्थापना करता है साथ ही वहां हिंदी अध्यापक पढ़ाने जाते हैं। मंत्रालय में 55 विभाग और 150 अनुभाग हैं जिनमें अनुवाद कार्य बहुत होता है। विदेशों में तैनाती के कारण आंकड़ों में कमी है जिसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.67 विधायी विभाग

मंत्रालय के अधिकारी ने नियम 5 के उल्लंघन की विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि विभाग में अधिनियम और बिल का अनुवाद कार्य बहुत होता है तथा कार्य को समयानुसार पूर्ण करने हेतु अधिकारी/कर्मचारी नहीं है। उन्होंने रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी दी। विधायी विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है।

13.68 विधि कार्य विभाग

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमित व्यक्त की तथा आंकड़ों को बेहतर करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने बताया कि विभाग में सभी कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान है। अधिकारी ने जानकारी दी कि विभाग ने लगभग 7500 विधिक शब्दों का शब्दकोश तैयार किया है जिसे हम राजभाषा विभाग के साथ साझा भी करेंगे। विधि कार्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है।

13.69 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड की वजह से आंकड़ों में कमी दर्ज हुई है तथा हम इसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय में अनुवाद कार्य की अधिकता है, इस प्रयोजन हेतु अधिकारी के रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी दी। समिति का गठन विचाराधीन है।

13.70 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की तथा आश्वासन दिया कि पत्राचार और टिप्पण के प्रतिशत को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अधिकारी ने वेबसाइट को भी अद्यतित करने का आश्वासन दिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाना है।

13.71 संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पत्राचार में आई थोड़ी कमी का कारण कार्य की गोपनीय प्रकृति है। उन्होंने बताया की आयोग में बहुत अनुशासनात्मक कार्यों की अधिकता के कारण भी लक्ष्य से थोड़ा पीछे है। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे आंकड़ो को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वेबसाइट को भी अद्यतित करने का आश्वासन दिया। आयोग के अधिकारी ने रिक्त पदों को भरने का निवेदन किया। संघ लोक सेवा आयोग की हिंदी सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

13.72 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने आंकड़ों पर सहमति व्यक्त की तथा उन्होंने कहा कि डाटा रिपोर्टिंग ठीक प्रकार से नहीं की गई है, जिसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संशोधित रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने का निवेदन किया। वेबसाइट को अद्यतित करने का भी आश्वासन दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.73 सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय में 05 उच्च अधिकारी शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करते हैं। साथ ही जानकारी दी कि मंत्रालय हिंदी पखवाड़ा भी बड़े उल्लास से मनाता है। अधिकारी ने वेबसाइट की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है।

13.74 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय के आंकड़ें गत वर्ष की तुलना मे काफ़ी बेहतर है। मंत्रालय में चार उच्च अधिकारी शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करते हैं। मंत्रालय के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अगली तिमाही में हम आंकड़ों को और बेहतर करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि वे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अपने अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारियों को बुलाते हैं। उपस्थित अधिकारी ने जानकारी दी कि ई-ऑफिस में "क्विक नोटिंग" का विकल्प है जिसमें हिंदी के कई वाक्य उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग हम हिंदी की नोटिंग में करते हैं। रिक्त पदों को भरने का भी निवेदन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.75 संस्कृति मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में अति विशिष्ट संदर्भ से संबंधित कार्य हिंदी में ही होता है। उन्होंने जानकारी दी कि मंत्रालय में वर्ष में चार कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय में प्राध्यापक राजभाषा हिंदी व नीति से संबंधित व्याख्यान देते हैं। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था। संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.76 संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय के आंकड़ों की सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय को कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। वेबसाइट के बारे में अधिकारी ने जानकारी दी कि मंत्रालय में सभी अनुभाग हिंदी संस्करण को स्वयं अद्यतित करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.77 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) और नियम 5 के उल्लंघन पर अधिकारी ने सहमति व्यक्त की। अधिकारी ने इस विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया। वेबसाइट को भी अद्यतित करने की बात कही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा धारा 3(3) और नियम 5 के उल्लंघन को बड़ी ही गंभीरता से लिया गया।

13.78 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और आंकड़ों को बेहतर करने का आश्वासन दिया। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में कई पद खाली हैं जिसे भरने का अनुरोध किया गया। वेबसाइट को भी जल्द ही अद्यतित करने की बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

13.79 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मंत्रालय के अधिकारी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। मंत्रालय के द्वारा धारा 3(3) और नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे इस त्रुटि को जल्द ही दूर करेंगे। वेबसाइट को भी अद्यतित करने का आश्वासन दिया। इनकी 2021-22 की तिमाही की रिपोर्ट में भी कमी पाई गई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के गठन की कोई सूचना नहीं मिली है।

बैठक के मुख्य सुझाव/निर्णय

i. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाए ताकि बैठक में नीति संबंधी निर्णय लिए जा सकें।

(कार्रवाई- सभी मंत्रालय/विभाग)

ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट में सही एवं वास्तविक/तथ्यात्मक आंकड़े भरे जाएं।

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

iii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

(कार्रवाई – कार्यान्वयन-2 अनुभाग/ एनआईसी, राजभाषा विभाग)

iv. मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट द्विभाषी रुप में तैयार की जाए एवं अंग्रेजी के साथ-साथ इसे हिंदी में भी अद्यतित किया जाए।

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

v. मंत्रालय/विभाग द्वारा धारा 3(3) एवं नियम 5 का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

vi. मंत्रालय/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके अधीनस्थ कार्यालय अपने क्षेत्र में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लें।

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

vii. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाए। जिस मंत्रालय/विभाग में हिंदी के पद कम हैं, वे अपने यहां पद सृजित कराकर प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेजें। विभाग उन्हें केन्द्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग में इनकैडर करेगा।

(कार्रवाई – सेवा अनुभाग, राजभाषा विभाग)

viii. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध प्राप्त होने पर एनआईसी, राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध कराया जाए।

(कार्रवाई –एनआईसी, राजभाषा विभाग)

ix. कंठस्थ टूल पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों का नामांकन किया जाए एवं उन्हें प्रशिक्षित करवाया जाए।

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

x. मंत्रालय/विभाग में हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाए और उनकी बैठकें आयोजित की जाएं।

(कार्रवाई – सभी मंत्रालय/विभाग)

बैठक समाप्त करते हुए संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा जुलाई 2022 में कॉलिक की 44वीं बैठक का आयोजन किया जाना संभावित है।

दिनांक 15 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के प्रथम चरण में विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	अंतरिक्ष विभाग
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
3.	आयुष मंत्रालय
4.	आर्थिक कार्य विभाग
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7.	इस्पात मंत्रालय
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 15 फरवरी, 2022 को अपराह्न 3:00 - 5:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के द्वितीय चरण में विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	उर्वरक विभाग
2.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
3.	औषध विभाग
4.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
5.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
6.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
7.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
8.	कोयला मंत्रालय
9.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
11.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)

दिनांक 16 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के प्रथम चरण भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	खान मंत्रालय
2.	ग्रामीण विकास विभाग
3.	गृह मंत्रालय
4.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
5.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
6.	डाक विभाग
7.	दूर संचार विभाग
8.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
9.	न्याय विभाग
10.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
11.	वस्त्र मंत्रालय
दिनांक 16 फरवरी, 2022 को अपराह्न 3:00 - 5:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	नागर विमानन मंत्रालय
2.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
3.	नीति आयोग
4.	पंचायती राज मंत्रालय
5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
7.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
8.	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	पर्यटन मंत्रालय
10.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

दिनांक 17 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
2.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग
4.	पोत परिवहन मंत्रालय
5.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
6.	भूमि संसाधन विभाग
7.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय
8.	भारत निर्वाचन आयोग
9.	भारी उद्योग विभाग
10.	मंत्रिमंडल सचिवालय
दिनांक 17 फरवरी, 2022 को अपराह्न 3:00 - 5:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
3.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग
4.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
5.	रेल मंत्रालय
6.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
7.	राजस्व विभाग
8.	लोक उद्यम विभाग
9.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

दिनांक 18 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	व्यय विभाग
2.	वाणिज्य विभाग
3.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
4.	वित्तीय सेवाएं विभाग
5.	विद्युत मंत्रालय
6.	विदेश मंत्रालय
7.	विधायी विभाग
8.	विधि कार्य विभाग
9.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
दिनांक 18 फरवरी, 2022 को अपराह्न 3:00 - 5:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
2.	संघ लोक सेवा आयोग
3.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6.	संस्कृति मंत्रालय
7.	संसदीय कार्य मंत्रालय
8.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
9.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
10.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

परिशिष्ट - क (31)

धारा 3(3)/नियम 5 का उलंघन करने वाले मंत्रालय/विभाग		
क्र. सं.	मंत्रालय के नाम	धारा 3(3) का उलंघन
	दूर संचार विभाग	2019-20 तथा 2020-21 दोनों वर्षों में उलंघन
	मंत्रालय के नाम	नियम 5 का उलंघन
1	आर्थिक कार्य विभाग	2019-20 तथा 2020-21 दोनों वर्षों में उलंघन
2	नीति आयोग	2019-20 तथा 2020-21 दोनों वर्षों में उलंघन
3	दूर संचार विभाग	2019-20 तथा 2020-21 दोनों वर्षों में उलंघन

सर्वाधिक हिंदी पत्राचार/हिंदी टिपण्णी करने वाले मंत्रालय/विभाग		
क्रं. सं.	मंत्रालय के नाम	हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता
1	संसदीय कार्य मंत्रालय	99.28
2	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	94.81
3	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय	92.66
4	वित्तीय सेवाएं विभाग	91.69
5	इस्पात मंत्रालय	89.31
क्रं. सं.	मंत्रालय के नाम	हिंदी टिपण्णी की प्रतिशतता
1	संसदीय कार्य मंत्रालय	84.4
2	रेल मंत्रालय	82.14
3	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय	79.62
4	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	79.29
5	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	75.34

सबसे कम हिंदी में पत्राचार/हिंदी टिपण्णी करने वाले मंत्रालय/विभाग		
क्रं. सं.	मंत्रालय के नाम	हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता
1	विदेश मंत्रालय	9.92
2	आयुष मंत्रालय	17.09
3	मंत्रिमंडल सचिवालय	25.19
4	पोत परिवहन मंत्रालय	35.91
5	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	37.18
क्रं. सं.	मंत्रालय के नाम	हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता
1	विदेश मंत्रालय	6.32
2	आयुष मंत्रालय	14.91
3	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	17.88
4	पोत परिवहन मंत्रालय	19.93
5	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	20.53

वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान मंत्रालयों द्वारा अपलोड किए गए क्यूपीआर की सं.

क्र.सं.	ऑफिस कोड	रिपोर्ट की संख्या	कार्यालय का नाम
1	mndl1027	3	राजस्व विभाग
2	mndl1048	3	पेयजल और स्वच्छता विभाग
3	mndl1129	3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
4	mndl1093	3	डाक विभाग
5	mndl1137	3	रक्षा उत्पादन विभाग
6	mndl1022	2	व्यय विभाग
7	mndl1013	3	संघ लोक सेवा आयोग
8	mndl1038	3	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
9	mndl1154	3	भूमि संसाधन विभाग
10	mndl1086	3	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
11	mndl1020	3	नीति आयोग
12	mndl1003	3	खान मंत्रालय
13	mndl1032	3	पेयजल और स्वच्छता विभाग
14	mndl1036	3	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
15	mndl1034	3	संसदीय कार्य मंत्रालय
16	mndl1157	3	पंचायती राज मंत्रालय
17	mndl1066	3	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
18	mndl1225	3	पोत परिवहन मंत्रालय
19	mndl1120	3	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
20	mndl1092	2	आर्थिक कार्य विभाग
21	mndl1181	2	ग्रामीण विकास विभाग
22	mndl1133	3	कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग
23	mndl1348	3	इस्पात मंत्रालय
24	mndl1163	3	वस्त्र मंत्रालय
25	mndl1091	2	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
26	mndl1090	2	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
27	mndl1010	3	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
28	mndl1113	3	रेल मंत्रालय
29	mndl1131	3	वित्तीय सेवाएं विभाग
30	mndl1468	3	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
31	mndl1114	3	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
32	mndl1106	2	पर्यटन मंत्रालय
33	mndl1498	2	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
34	mndl1358	2	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
35	mndl1134	3	आयुष मंत्रालय
36	mndl1158	3	विधि कार्य विभाग
37	mndl1330	3	भारी उद्योग विभाग
38	mndl1248	2	उर्वरक विभाग

39	mndl1115	2	विधायी विभाग
40	mndl1388	1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
41	mndl1533	3	पशुपालन,डेयरी विभाग
42	mndl1125	2	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
43	mndl1153	3	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
44	mndl1603	3	न्याय विभाग
45	mndl1464	3	विद्युत मंत्रालय
46	mndl1450	3	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
47	mndl1355	2	विदेश मंत्रालय
48	mndl1598	3	लोक उद्यम विभाग
49	mndl1148	3	भारत निर्वाचन आयोग
50	mndl1151	3	नागर विमानन मंत्रालय
51	mndl1570	2	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
52	mndl1586	3	श्रम और रोजगार मंत्रालय
53	mndl1123	3	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
54	mndl1419	3	उपभोक्ता मामले विभाग
55	mndl1221	3	वाणिज्य विभाग
56	mndl1601	3	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
57	mnkn1100	3	अंतरिक्ष विभाग
58	mndl1553	3	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
59	mndl1229	3	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
60	mndl1171	3	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
61	mndl1466	3	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
62	mndl1582	3	गृह मंत्रालय
63	mndl1524	3	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय
64	mndl1532	2	जनजातीय कार्य मंत्रालय
65	mndl1595	1	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
66	mndl1175	3	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
67	mndl1234	3	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
68	mndl1352	3	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
69	mndl1594	2	कोयला मंत्रालय
70	mndl1304	2	औषध विभाग
71	mndl1593	3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
72	mndl1356	3	संस्कृति मंत्रालय
73	mndl1362	3	मंत्रिमंडल सचिवालय
74	mndl1602	3	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
75	mndl1578	3	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
76	mnmh1361	3	परमाणु ऊर्जा विभाग

अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 15 फरवरी से 18 फरवरी, 2022 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	अधिकारी का नाम तथा पदनाम
1.	अंतरिक्ष विभाग	सुश्री संध्या शर्मा अपर सचिव
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सुश्री ऋचा शंकर उप महानिदेशक
3.	आयुष मंत्रालय	श्री रोहतास धनखड़ उप सचिव
4.	आर्थिक कार्य विभाग	सुश्री अनु.पी. मथाई संयुक्त सचिव
5.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	श्री आनंद प्रकाश निदेशक
6.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री भुवनेश कुमार संयुक्त सचिव
7.	इस्पात मंत्रालय	सुश्री आस्था जैन उप निदेशक
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री विजय बाल्यान उप सचिव
9.	उपभोक्ता मामले विभाग	श्री अशोक कुमार सहायक निदेशक
10.	उर्वरक विभाग	सुश्री अपर्णा शर्मा संयुक्त सचिव
11.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	श्री राजेश कुमार सिंह संयुक्त सचिव
12.	औषध विभाग	श्री प्रवीण कुमार उप सचिव
13.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	श्री पी.राममूर्ति उप सचिव श्री परमजीत यादव सहायक निदेशक

14.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	**सुश्री शुभा ठाकुर** **संयुक्त सचिव**
15.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री बाल्मीकि प्रसाद निदेशक
16.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सुश्री उर्मिला संयुक्त निदेशक (रा.भा)
17.	कोयला मंत्रालय	श्री मनोज कुमार सिन्हा उप निदेशक
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	श्री देवेन्द्र.एस. ऊइके उप सचिव
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**श्री मिन्हाज आलम** **संयुक्त सचिव**
20.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)	**श्री इकराम रिज़वी** **संयुक्त सचिव**
21.	खान मंत्रालय	**श्री शकील आलम** **आर्थिक सलाहकार** सुश्री पुष्पलता उप निदेशक(का.)
22.	ग्रामीण विकास विभाग	श्री तरूण कुमार सहायक निदेशक
23.	गृह मंत्रालय	श्री राकेश कुमार निदेशक
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	**श्री शिव सिंह मीना** **आर्थिक सलाहकार** श्री वेद प्रकाश मीना उप निदेशक(रा.भा)
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	**श्री आर.सतीश** **आर्थिक सलाहकार** श्री विजय सिंह मीना निदेशक(रा.भा)
26.	डाक विभाग	**डॉ. अमरप्रीत दुग्गल** **संयुक्त सचिव** श्रीमती सुनीता सिंह उप निदेशक

27.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	श्री ब्रिजमोहन लाल सारस्वत सहायक निदेशक
28.	न्याय विभाग	श्री अनिल शर्मा उप सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह परामर्शदाता
29.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री अमिताभ साहा उप सचिव श्री नन्दन सिंह दुग्गल उप निदेशक
30.	वस्त्र मंत्रालय	श्रीमती अंशु गुप्ता सहायक निदेशक
31.	नागर विमानन मंत्रालय	श्री पीयूष श्रीवास्तव वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
32.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	डॉ. शैलेन्द्र कुमार संयुक्त सचिव
33.	नीति आयोग	श्री शशि पाल निदेशक श्री सूरज प्रकाश बडगूजर उप निदेशक(रा.भा) श्री राम बाबू वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
34.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री विजय कुमार वेहरा आर्थिक सलाहकार श्री बद्रा सिंह सहायक निदेशक
35.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सुश्री शोभना श्रीवास्तव उप निदेशक(रा.भा)
36.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	सुश्री इंदिरा मूर्ति संयुक्त सचिव
37.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	श्री निरंजन चौधरी संयुक्त सचिव श्री धर्मवीर

		सहायक निदेशक श्री सुधीर कुमार सिन्हा अवर सचिव
38.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री सेलवम एस जी अवर सचिव श्रीमती रिमझिम गुप्ता सहायक निदेशक
39.	पर्यटन मंत्रालय	श्रीमती संतोष सिल्पोकर संयुक्त निदेशक(रा.भा)
40.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**डॉ. सतीश चन्द्र गठकोठी** **वैज्ञानिक 'जी'/ सलाहकार** सुश्री वीना शर्मा उप निदेशक(रा.भा)
41.	दूर संचार विभाग	श्री बालचन्द्र अय्यर उप महानिदेशक श्री रामानुज डे उप सचिव(रा.भा) श्री पी.सी विश्वकर्मा परामर्शदाता
42.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	सुश्री सरोज गिरी सहायक निदेशक
43.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	सुश्री रुचिर मित्तल निदेशक सुश्री मंजु गुप्ता सहायक निदेशक
44.	पशुपालन और डेयरी विभाग	श्री मुस्तफा हुसैन उप निदेशक(रा.भा) सुश्री स्वाति मेल्टी सहायक निदेशक
45.	पोत परिवहन मंत्रालय	श्री राकेश कुमार वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
46.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	श्री जय प्रकाश मीणा उप सचिव श्री निखिल अरोड़ा सहायक निदेशक

47.	भूमि संसाधन विभाग	श्री कर्मचन्द उप सचिव श्री कन्हैया प्रसाद लाल सहायक निदेशक
48.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय	श्री कमल जीत सिंह रामुवालिया प्रधान निदेशक सुश्री अनामिका अंतिल (स.प्र.अ.) सुश्री मीनाक्षी (स.प्र.अ.)
49.	भारत निर्वाचन आयोग	सुश्री रचना गुप्ता निदेशक (रा.भा) श्री नीरज कुमार सहायक निदेशक (रा.भा)
50.	भारी उद्योग विभाग	श्री जितेन्द्र सिंह संयुक्त सचिव श्री कुमार राधरमण सहायक निदेशक
51.	मंत्रिमंडल सचिवालय	श्री सौमित्र सबर अवर सचिव श्री धर्मवीर अंतिल
52.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	श्री सत्यमूर्ति नागेश उप निदेशक श्री सुखलाल मीना उप सचिव
53.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	श्री सुन्दर सिंह उप सचिव श्री फूल कंवर सहायक निदेशक सुश्री प्रीति थापा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
54.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	श्री प्रवीण कुमार शर्मा सहायक निदेशक श्री काले खां सहायक निदेशक

55.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग	**श्री विशाल गगन** **संयुक्त सचिव** डॉ. राकेश कुमारी निदेशक
56.	रेल मंत्रालय	डॉ. वरूण कुमार निदेशक(रा.भा) सुश्री सरिता दत्ता सहायक निदेशक
57.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	श्री राकेश कुमार उप निदेशक श्री सुनील कुमार
58.	राजस्व विभाग	सुश्री प्रीति सैलारे सहायक निदेशक डॉ. सतीश चन्द्र परामर्शदाता
59.	लोक उद्यम विभाग	श्री मुनी राम मीना उप सचिव सुश्री अर्चना रांगडा उप निदेशक श्री राजबीर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
60.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	**श्री सुरिन्द्र पाल सिंह** **संयुक्त सचिव** श्री आनन्द भोई उप निदेशक (रा.भा)
61.	व्यय विभाग	श्री शिव राम मीना निदेशक श्री एम.एन. मीना निदेशक श्री राजेश्वर कुमार उप निदेशक
62.	वाणिज्य विभाग	श्री सुबोध कुमार निदेशक

63.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	श्री जी. श्रीनिवासन उप सचिव श्री के.एन. सिंह सहायक निदेशक
64.	वित्तीय सेवाएं विभाग	श्री संजय कुमार उप सचिव श्री भीम सिंह उप निदेशक(रा.भा)
65.	विद्युत मंत्रालय	**श्री विशाल कपूर** **संयुक्त सचिव** श्री अनिल कुमार सहायक निदेशक श्री अमित प्रकाश सहायक निदेशक श्री अशोक बाबू वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
66.	विदेश मंत्रालय	**श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल** **संयुक्त सचिव** श्री मोहन लाल मीणा सहायक निदेशक
67.	विधायी विभाग	डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह अपर विधायी परामर्शी श्री जगमाल सिंह परामर्शी
68.	विधि कार्य विभाग	**श्रीमती अंजु राठी राणा** **अपर सचिव** सुश्री सविता सिंह उप निदेशक(रा.भा) सुश्री अधुसीना घोष कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी सुश्री इंदु वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
69.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**श्री नागेश कुमार सिंह** **उप महानिदेशक** श्री निकोलस खालखो

		उप निदेशक सुश्री नीलम सहायक निदेशक
70.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**सुश्री माया पाण्डेय** **उप सचिव** सुश्री सरिता कुंवर उप निदेशक(रा.भा)
71.	संघ लोक सेवा आयोग	**श्री मुकेश लाल** **संयुक्त सचिव** सुश्री तरूणा जंगपांगी निदेशक(रा.भा)
72.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**श्री पी.के. अब्दुलकरीम** **आर्थिक सलाहकार** श्री इफ्तेखार अहमद उप निदेशक(रा.भा) श्री कौंचोग धेरोय व.अनु. अधिकारी
73.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**श्री कमलेश चतुर्वेदी** **संयुक्त सचिव** श्री परेश कुमार गोयल निदेशक श्री नरेश रजक
74.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	श्री परमानन्द आर्य निदेशक श्री दिलीप कुमार निगम उप निदेशक(रा.भा)
75.	संस्कृति मंत्रालय	**सुश्री संजुक्ता मुदगल** **संयुक्त सचिव** डॉ. आर.रमेश आर्य निदेशक
76.	संसदीय कार्य मंत्रालय	सुश्री सुमन सुचिता बारा निदेशक श्री विरेन्द्र कुमार सहायक निदेशक डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव

77.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**श्री तनवीर कमर मोहम्मद** **संयुक्त सचिव** **श्री गंगा कुमार** **उप महानिदेशक** श्री संदीप शर्मा निदेशक श्री राकेश वरि.अनु.अधिकारी श्री रमेश चन्द्र वरि.अनु.अधिकारी
78.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	**श्री प्रभुदास खलखो** **संयुक्त सचिव** श्री लालूराम लाम्बा सहायक निदेशक
79.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	**श्री शान्तेनु मित्र** **वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार** श्री अविनाश ठाकुर कनि.अनु.अधिकारी

अनुलग्नक – 'ग'

दिनांक 15 फरवरी से 18 फरवरी, 2022 के दौरान आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक में राजभाषा विभाग के उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रं.सं	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री अंशुली आर्य	सचिव
2.	डॉ. मीनाक्षी जौली	संयुक्त सचिव
3.	श्री बाबू लाल मीना	निदेशक (का./सेवा)
4.	डॉ. धनेश द्विवेदी	उप संपादक (पत्रिका)
5.	सुश्री अभिलाषा मिश्रा	उप निदेशक (का-2)
6.	श्री राजेश श्रीवास्तव	उप निदेशक (तकनीकी)
7.	श्री रघुवीर शर्मा	सहायक निदेशक (अनुसंधान)
8.	श्री संतोष कुमार	अनुसंधान अधिकारी (का.)
9.	श्री दीपक कुमार	निरीक्षक (तकनीकी)
10.	श्री केवल कृष्ण	वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार (एनआईसी)
11.	श्री बलराज सिंह	अवर श्रेणी लिपिक
12.	श्री विकास वागड़ी	डीईओ
13.	श्री जितेन्द्र कुमार	एमटीएस